नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 069
दि. 11.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

जेन जी आंदोलन की जांच तेज, पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की जबरन पेशी की तैयारी

(जीएनएस)। नेपाल में जेन जी आंदोलन के दौरान पुलिस बल द्वारा कथित अत्यधिक शक्ति प्रयोग की जांच अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। न्यायिक आयोग, जो इस पूरे मामले की सुनवाई और तथ्य संग्रह कर रहा है, अब उन वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की ओर बढ़ रहा है जिनकी भूमिका और आदेशों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा अब तक अपना बयान दर्ज न कराए जाने को अत्यंत गंभीर मानते हुए उन्हें कानूनी रूप से पेश कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के कार्यकाल में केवल दो सप्ताह शेष रह गए हैं, जबकि राजनीतिक स्तर के कई महत्वपूर्ण बयान अभी भी लंबित पड़े हैं, ऐसे में आयोग ने प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा ने बताया कि अब तक लगभग 150 अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। फील्ड में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से प्रारंभिक पूछताछ पूरी होने के बाद अब आयोग की फोकस वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा शीर्ष पदों पर मौजूद अधिकारियों पर है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली, पूर्व गृहमंत्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल और नेपाल पुलिस प्रमुख दानबहादुर कार्की के बयान इस जांच के लिए अनिवार्य हैं और इनके बिना पूरी प्रक्रिया अधूरी बनी रहेगी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग की सिफारिश पर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उन्हें बिना अनुमति काठमांडू से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली पहले ही यह कह चुके हैं कि वे आयोग को असंवैधानिक

मानते हैं और इसके समक्ष बयान देने का कोई आधार नहीं देखते, जिसके चलते मामला और अधिक टकरावपूर्ण हो गया है।

आयोग के प्रवक्ता शर्मा ने साफ कहा कि बयान प्रक्रिया से पीछे हटने का कोई कानूनी आधार नहीं है और यदि दोनों नेता आयोग के समक्ष स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होते, तो उन्हें पेश कराने के लिए बाध्यकारी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आयोग सरकार से अनुरोध कर सकता है कि आवश्यक होने पर पुलिस बल की मदद से उन्हें आयोग के सामने उपस्थित कराया जाए। इसी दिशा में गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि आयोग औपचारिक अनुरोध करता है तो सरकार कानून के अनुसार पुलिस को तैनात कर दोनों नेताओं को आयोग के समक्ष लाएगी। गृहमंत्री का कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और किसी भी व्यक्ति की हैसियत या पद को देखते हुए इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

हालाँकि दूसरी ओर नेकपा (एमाले) के उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ने आयोग की वैधता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह आयोग ही अवैध और पक्षपाती है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री ओली के वहाँ उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञवाली का दावा है कि आयोग राजनीतिक प्रेरणा से संचालित है और इसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। इसी राजनीतिक विवाद के बीच आयोग ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल का बयान दर्ज कर लिया है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा तलब करने की संभावना भी व्यक्त की है। पूर्व पुलिस प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुंग को भी फिर से बुलाए जाने की आशंका जताई जा रही है।

जेन जी आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई नेपाल की राजनीति, प्रशासन और सुरक्षा ढांचे को गहराई से प्रभावित करने वाला विषय बन चुका है। आयोग की जांच जैसे-जैसे अपने अंतिम चरण में पहुँच रही है, राजनीतिक तनाव भी उतना ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृहमंत्री को वास्तव में आयोग के सामने पेश किया जाएगा या यह विवाद नेपाल की राजनीति को एक नए मोड़ की ओर ले जाएगा।

राजकोट में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार, देश में फिर गरजी न्याय की मांग

(जीएनएस)। राजकोट। गुजरात के राजकोट जिले में एक भयावह और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया है। अटकोट थाना क्षेत्र के पास एक गांव में 6 साल और आठ महीने की मासूम बच्ची के साथ अत्यधिक क्रूरता का मामला सामने आया। घटना की गंभीरता और समय पर पुलिस की कार्रवाई ने इसे राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। घटना 4 दिसंबर को हुई जब बच्ची अपने माता-पिता के खेत में खेल रही थी और उनके परिवार के सदस्य खेत में मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची का अपहरण किया और उस पर हमला किया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, उन्होंने तुरंत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की खोज में 10 जांच टीमों का गठन किया।

पुलिस जांच में लगभग 100 संदिग्धों से पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया और पुलिस ने उसे रामसिंह तेरसिंह के रूप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ

कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। बच्ची को त्वरित प्राथमिक चिकित्सा के लिए राजकोट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति अब धीरे-धीरे स्थिर बताई जा रही है।

यह मामला 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली निर्भया कांड की याद दिलाता है, जिसमें एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उस पर क्रूरता की गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे घटनाएं समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

राजकोट पुलिस की तत्परता और जांच में तेजी ने यह सुनिश्चित किया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, निगरानी और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा उपाय बढ़ाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की घोषणा की है।

इस घटना ने एक बार फिर देशभर में बच्चों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर बहस को तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और सुरक्षा प्रणालियों का सुदृढ़ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजकोट की इस घटना ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई और सतर्कता की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है।

सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां और 125 कर्मी जुटे आग बुझाने में

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर में बुधवार की सुबह एक बार फिर भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसने शहरवासियों को सकते में डाल दिया। आग राज टेक्सटाइल मार्केट में लगी, जो शहर का प्रमुख कपड़ा हब माना जाता है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत 15 से अधिक फायर टेंडर मौके पर भेजे। आग इतनी भयानक थी कि मार्केट में धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया। आग तेजी से फैलने के कारण कई दुकानों और गोदामों में लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया।

सूरत के चीफ फायर अफसर बसंत परिक ने बताया कि आग करीब 7 बजकर 14 मिनट पर लगी और इसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कुल मिलाकर इस आपरेशन में 22 फायर टेंडर और 100 से 125 फायर अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि आग अब पूरी तरह नियंत्रण में है और वर्तमान में बिल्डिंग के अंदर कूलिंग का काम चल रहा है। गोदाम

में भरे भारी सामान के कारण अंदर प्रवेश करना मुश्किल है और कूलिंग में कुछ समय लग सकता है।

दमकल अधिकारी ने बताया कि आग ने कपड़ा बाजार को गंभीर क्षति पहुँचाई है। दुकानदारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है और प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों की संभावना जताई जा रही है।

सूरत की घटना के ठीक पहले दाहोद जिले में भी आग की घटना हुई। सिंगवाद तालुका के बरेला गांव में एक ही परिवार के पांच भाइयों के घर में आग लगी, जिसमें घर में बंधी चार बकरियां जलकर मारी गईं, जबकि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। गोधरा दमकल विभाग ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस आग में घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात में सर्दियों की शुरुआत और बढ़ते शॉर्ट सर्किट मामलों के चलते इस तरह की आग की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। सूरत और दाहोद की घटनाओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तत्काल प्रतिक्रिया और पर्याप्त दमकल संसाधन ही बड़े नुकसान को रोक सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने सभी प्रभावित दुकानदारों और परिवारों को राहत और पुनर्निर्माण के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया है।

इस बीच सूरत पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग लगने वाले इलाके को सुरक्षित कर दिया है और जांच में जुटी टीम घटनास्थल के सबूत इकट्ठा कर रही है। अधिकारी आग के संभावित कारणों की विस्तृत जांच कर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपायों पर भी ध्यान देंगे।

अलवर अस्पताल की घोर लापरवाही ने परिवार को दोहरी त्रासदी में डाल दिया, मृतक के अंतिम संस्कार में हुई भूल

(जीएनएस)। अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल परिवार को स्तब्ध कर दिया बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के एक परिवार को अपने बुजुर्ग परिजन के निधन की खबर मिली थी और उन्होंने विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली थी। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और अस्थि विसर्जन की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन दो दिन बाद जीआरपी थाना पुलिस की कॉल ने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें बताया गया कि उनका असली परिजन अभी भी जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस सूचना के बाद परिवार फिर से अस्पताल पहुंचा और उन्हें यह यकीन करना पड़ा कि उन्होंने गलती से किसी और का शव अंतिम संस्कार कर दिया।

मामला तब और जटिल हुआ जब जिले के उद्योग नगर और जीआरपी थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से दो बुजुर्गों के शव मिले। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में भेजा गया। इसी बीच राजगढ़ थाना क्षेत्र के परिजन पहचान प्रक्रिया के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मॉर्च्युरी में रखे एक शव को अपने मृतक परिजन का मान लिया। परिजन लंबे समय से घर से दूर काम कर रहे व्यक्ति की पहचान पहले से ही मुश्किल थी, और अस्पताल प्रशासन ने भी बिना पुष्टि किए शव सौंप दिया। परिणामस्वरूप परिवार ने विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर दिया।

लेकिन दो दिन बाद पुलिस ने परिवार को कॉल कर सूचित किया कि असली मृतक अभी भी अस्पताल में है। यह सुनते ही परिजन स्तब्ध रह गए और समझ गए कि उन्होंने किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम आमतौर पर 72 घंटे की पहचान अवधि पूरी होने के बाद किया जाता है, लेकिन इस मामले में पहचान और प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हुई।

परिजन अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शव सौंपने से पहले उचित पहचान और पुष्टि की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की जल्दबाजी और उदासीनता के कारण यह त्रासदी हुई। अस्पताल के अधिकारी इस मामले में अभी तक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं।

यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह अस्पतालों में मॉर्च्युरी संचालन और शव पहचान प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती है। परिवार को अब वास्तविक परिजन का शव प्राप्त कर उसे अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी, जिससे उनके दुख और पीड़ा में और वृद्धि हुई है।

मामले ने प्रशासनिक लापरवाही और मानवीय भूल के गंभीर परिणामों को सामने लाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर अस्पतालों को मॉर्च्युरी संचालन, शव पहचान और पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।

बाड़मेर में वीर बलवंत सिंह की प्रतिमा स्थापना, 1971 युद्ध की शौर्यगाथा का सम्मान

(जीएनएस)। बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाखासर गांव में 13 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलवंत सिंह बाखासर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह समारोह 1971 के भारत-पाक युद्ध में अद्वितीय वीरता और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बलवंत सिंह की याद में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कई जनप्रतिनिधि और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

बलवंत सिंह बाखासर का नाम वीरता और समाज सेवा का प्रतीक रहा। सीमावर्ती इलाके में जन्मे और पले-बढ़े बलवंत सिंह को 'रॉबिनहुड' के नाम से जाना जाता था। अकाल और कठिन परिस्थितियों में वह पाकिस्तानी डाकुओं से अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री छीनकर गरीबों और जरूरतमंदों में वितरित करते थे। उनकी यह सेवा और साहस स्थानीय लोगों के बीच उन्हें गरीबों का मसीहा बनाती थी। बाखासर का भौगोलिक महत्व भी विशेष था, जहां एक ओर पाकिस्तान की सीमा और दूसरी ओर गुजरात थी। इस रेगिस्तानी इलाके की कठिन परिस्थितियों में उनका अनुभव और जानकारियां अत्यंत उपयोगी साबित हुई। 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय इस इलाके की जिम्मेदारी जयपुर के पूर्व महाराजा और ब्रिगेडियर भवानी सिंह के हाथ में थी। बलवंत सिंह की क्षमताओं और इलाके की जानकारी से अवगत होकर भारतीय सेना ने उनसे सहयोग लिया। बलवंत सिंह ने भारतीय सेना के साथ मिलकर छाछरो की ओर रसद, असलहा और पानी पहुंचाने में मदद की। उनकी रणनीतिक समझ और कठिन रेगिस्तानी रास्तों की जानकारी ने भारतीय सेना को निर्णायक और सटीक हमले में सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने छाछरो पर नियंत्रण स्थापित किया, जो कई महीनों तक प्रशासनिक रूप से भारत के अधीन रहा। बाद में शिमला समझौते के तहत इसे वापस पाकिस्तान को सौंपा गया।

बलवंत सिंह की वीरता और लोकसेवा को अमर बनाने के लिए बाखासर में बलवंत चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अनावरण समारोह में बलवंत सिंह के परिवारजन, पूर्व सैनिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। साथ ही समारोह में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। बाखासर के ग्रामीण इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं और इसे अपने इलाके की गौरवगाथा का प्रतीक मानते हैं।

इस प्रतिमा स्थापना से न केवल बलवंत सिंह के योगदान को याद किया जाएगा, बल्कि नई पीढ़ी के लिए देशभक्ति, वीरता और सेवा का आदर्श भी स्थापित होगा। उनका जीवन यह संदेश देता है कि साहस और समाज सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी धरोहर को अमर बना सकता है और राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संपादकीय

धनी देशों की तंगदिली से बढ़ेगी मृत्यु दर

इस सदी के ढाई दशक में बाल मृत्यु दर घटने को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जतायी जा रही है। गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है दुनिया भले ही अमीर हो गई है लेकिन गरीब देशों के बच्चों पर होने वाला खर्च घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खर्च पर 27 फीसदी की कटौती की गई है। जिससे इस वर्ष दो लाख अतिरिक्त बच्चों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, ये मौतें उन बीमारियों से हो सकती हैं, जिन्हें अमीर देशों से मिलने वाली मदद से होने वाले टीकाकरण और बुनियादी इलाज से टाला जा सकता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं कि जिस समय दुनिया में संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस समय गरीब देशों के बच्चों पर स्वास्थ्य खर्च का घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आशंका जतायी जा रही है कि यदि स्वास्थ्य सहायता में तीस प्रतिशत की कटौती हो जाती है तो वर्ष 2045 तक 1.6 करोड़ अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। विडंबना देखिए कि इस आसन्न संकट को नजरअंदाज करके विकसित देश अपने रक्षा व आंतरिक खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि अमीर देशों द्वारा गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दिया जाने वाला पैसा उनके बजट के एक फीसदी से भी कम है। गेट्स फाउंडेशन का विश्व के अमीर देशों से आग्रह है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें, जहां वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं। दरअसल, संकट में वे बच्चे हैं, जो अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस संकट बढ़ने से दशकों से हासिल वैश्विक प्रगति बेकार हो जाएगी। निस्संदेह, दुनिया में कहीं भी पैदा हुए बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए।

दरअसल, गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स रिपोर्ट और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बताया कि 2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की पांचवें जन्मदिन से पहले मौत हो गई थी। आशंका है कि आर्थिक मदद में कटौती से इस वर्ष इस संख्या में दो लाख की वृद्धि से इसके बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की आशंका है। जिसकी मूल वजह स्वास्थ्य के लिये वैश्विक मदद में आई बड़ी गिरावट है। इस वर्ष सहायता निधि में भारी कटौती के अलावा गरीब देशों के बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम के चलते मलेरिया, एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध हासिल उपलब्धियों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट बताती है कैसे प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश से सीमित बजट में लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। निस्संदेह, गरीब मुल्कों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स कहते हैं विश्व में गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये वित्तीय संसाधन बढ़ाने व वर्तमान सिस्टम में सुधार हेतु दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी के दामन पर दाग लगेगा कि मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार की पहुंच के बावजूद हम लाखों बच्चों का जीवन बचाने के लिये धन नहीं जुटा पाए। हम सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके बाल मृत्यु दर वृद्धि को रोक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम वर्ष 2045 तक कई मिलियन बच्चों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी होगा कि हम विदेशी मदद का अधिकतम उपयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता के टीके और डेटा के नये उपयोग पर अधिक ध्यान दें। निस्संदेह, इन बीमारियों से लड़ने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को जारी रखने की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन का मानना है कि अगली पीढ़ी के नवाचारों के विकास में निवेश से हम बच्चों में होने वाले मलेरिया और निमोनिया जैसे कुछ घातक रोगों को हमेशा के लिये खत्म कर सकते हैं।

ट्रंप के शांति समझौते को नकार फिर संघर्ष

> “अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की थी कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ‘ऐतिहासिक’ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिये हैं। ट्रम्प ने उसे आधार बनाकर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी ठोक दी। अब इसका मज़ाक़ बनना शुरू हो चुका है।

ट्रंप ने जिस युद्ध विराम के हवाले से नोबेल पीस प्राइज़ पाने की दावेदारी ठोकी थी, वो एक झटके में एक्सपोज़ हो गई है। युद्ध विराम इतनी जल्दी टूट जायेगा, इसकी आशा व्हाइट हॉउस को भी नहीं थी। 8 दिसंबर को फिर से हुई झड़पों के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। महीनाभर पहले 10 नवंबर को एक थाई सैनिक के लैंडमाइन से घायल होने के बाद से तनाव बढ़ गया था। कंबोडिया का आरोप है कि वह कई सौ किलोमीटर तक फैली एक साझा सीमा के कई विवादित हिस्सों पर थाई हमले का शिकार है। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थाई गोलाबारी में सात कंबोडियन नागरिक मारे गए हैं और 20 अन्य घायल हुए हैं। दूसरी ओर बैंकॉक ने नोम पेन्ह पर आरोप लगाया है, कि व्हाइट हाउस द्वारा खून-खराबा रोकने की चेतावनी के बावजूद उसने बॉर्डर पार रॉकेट हमले किए।

कंबोडिया की सीमा कुल तीन देशों से मिलती है। पश्चिम और उत्तर में थाईलैंड है, तो उत्तर में लाओस स्थित है। पूर्व और दक्षिण पूर्व में वियतनाम है तो दक्षिण में कंबोडिया की सीमा थाईलैंड की खाड़ी से मिलती है। 9 नवंबर, 1953 को फ्रांस ने कंबोडिया को आजाद कर दिया। वर्ष 1863 से 1953 के कालखंड में कंबोडिया पर फ्रांस के कब्ज़े के दौरान ही थाईलैंड (जिसे उस समय सियाम कहा जाता था) के साथ कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थीं, विशेषकर 1907 के सीमा निर्धारण में, जिससे कई विवादित क्षेत्र बने, उनमें से एक है प्रीह विहियर मंदिर, जो आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है।

प्रीह विहियर मंदिर पर थाई-कंबोडियाई क्षेत्रीय विवाद 2008 में भड़क गया, जब थाई सरकार ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सह-हस्ताक्षर किया, जिसने मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए यूनेस्को को कंबोडिया के अनुरोध का समर्थन किया। इस कदम से थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यहां तक कि 2008 से 2011 की अवधि में दोनों देशों के बीच

सशस्त्र झड़पें भी हुईं।

इस साल अक्तूबर तक थाई-कम्बोडिया के बीच फुल स्केल वॉर में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और लगभग 40 हज़ार से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। विवाद से निपटारे के लिए द्विपक्षीय वार्ता विफल रही। आसियान द्वारा मध्यस्थता और शांति स्थापना प्रयासों के साथ भी यही हुआ। फिर आसियान सम्मेलन के दौरान 25 अक्तूबर, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की थी कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ‘ऐतिहासिक’ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिये हैं। ट्रम्प ने उसे आधार बनाकर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी ठोक दी। अब इसका मज़ाक़ बनना शुरू हो चुका है।

अब सवाल यह है, क्या ट्रंप केवल शांति समझौता का क्रेडिट लेने की जल्दी में थे? क्या उन्हें समस्या की तह तक नहीं जाना चाहिए था? ट्रंप इसी तरह शांति स्थापना की सतही घोषणा भारत-पाकिस्तान के सन्दर्भ में करते रहे हैं। यूक्रेन-रूस के बीच शांति प्रयासों का मज़ाक़ अलग बन रहा है। ट्रंप की तथाकथित शांति स्थापना से ग़ज़ा में शांति नहीं दिख रही। विश्लेषकों का कहना है कि युद्धविराम के बाद से गाजा में इस्राइल द्वारा फलस्तीनियों की हत्या की दर धीमी हो गई है, लेकिन युद्ध जारी है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता वाली योजना का दूसरा चरण करीब है। लेकिन मुख्य मुद्दों को अभी भी हल करने की ज़रूरत है। मतलब साफ़ है, ट्रम्प ने जहां-जहां शांति स्थापना का ढोल पीटा, वहां अशांति दोबारा भड़की है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच दोबारा से युद्ध छिड़ जाना ट्रम्प की विफलता का दूसरा उदाहरण है।

मलेशिया, जो अभी आसियान का चेयरमैन है, ने बीच-बचाव करने की पेशकश की थी। मगर, इस हड़बड़ी के विवाद में मलेशिया भी कम दोषी नहीं है। वह इसे डिप्लोमैटिक जीत मान रहा था, लेकिन उसने अंदर की अनसुलझी शिकायतों को नज़रअंदाज़ कर दिया। पिछली 25 अक्तूबर, 2025 को आत्ममुग्ध ट्रम्प ने सीज़फ़ायर की घोषणा के बाद, इसका पूरा क्रेडिट लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा था, ‘मैंने थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों टैरिफ धमकी के बाद शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। सभी को बधाई। मैंने अपनी ट्रेड टीम को बातचीत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है।’ अफ़सोस, सिर्फ 42 दिन बाद ट्रम्प के तथाकथित शांति समझौते की धज्जियां उड़ गईं।

ठीक से देखा जाये, तो उन दिनों चीन की भागीदारी ज़्यादा बारीक थी। चीन ने धमकाने की बजाय डिप्लोमैटिक ऑब्ज़र्वर तैनात करते हुए क्षेत्रीय संयम और आसियान प्रक्रिया का सम्मान करने की आम अपील की। 27 जुलाई, 2025 को विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था, ‘चीन दोनों तरफ हुए नुकसान से बहुत दुखी है और दिल से हमदर्दी दिखाता है। चीन बिना भेदभाव वाला रवैया बनाए रखेगा और सीज़फ़ायर के लिए अच्छी भूमिका निभाएगा।’ लेकिन दो दिनों की फायरिंग में जिस तरह चीनी हथियार मिले हैं, वो कुछ और कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं।

लेकिन, क्या कम्बोडिया और थाईलैंड धर्मयुद्ध लड़ रहे हैं। नहीं। एक सच यह भी है कि कम्बोडिया और थाईलैंड का झगड़ा प्रीह विहियर में भगवान शिव के प्रति आस्था को लेकर बिल्कुल नहीं है। कंबोडिया में डांगरेक पहाड़ों की चोटी पर स्थित प्रीह विहियर यूनेस्को-सूचीबद्ध हिंदू मंदिर है, जिसे 11वीं-12वीं सदी में खमेर साम्राज्य ने भगवान शिव को समर्पित किया था। यह प्राचीन मंदिर विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अद्भुत खमेर वास्तुकला से अधिक थाईलैंड के साथ सीमा विवाद और राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण सुर्खियों में है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन प्रथम और द्वितीय द्वारा किया गया था, जो खमेर साम्राज्य के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो कि राजा का समाधि स्थल भी है। यह स्थान मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर था; लेकिन कालांतर में 14वीं शताब्दी में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया।

मगर, एक सवाल कोई भी समझदार पूछेगा, मामला चूंकि शिवमंदिर से जुड़ा है तो भारत शांति प्रयासों के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ता? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मिलिट्री झड़प के बीच, भारत ने 26 जुलाई, 2025 को कहा था, ‘हम हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं, उम्मीद है कि यह जल्द खत्म हो जाएगा।’ भारत का लाइन ऑफ़ एक्शन अब भी बदला नहीं है!

प्रेरणा

प्रकृति की गोद में जन्मी प्रतिभा का अनकहा सफ़र

एंटोन चेखव के बचपन की यह कहानी केवल एक महान लेखक के जन्म की दास्तान नहीं, बल्कि यह उस सच्चे प्रेम की कहानी है जो एक बच्चे और प्रकृति के बीच बिना किसी शब्द के पनपता है। चेखव को जिस किंडरगार्टन में भेजा गया था, वहाँ प्रकृति प्रेम का नियम इस हद तक सख्त था कि बच्चों को फूलों को देखने और उनसे प्रेम जताने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें तोड़ने की मनाही थी। यह नियम बच्चों पर इतना हावी रहता था कि वे फूलों या पेड़ों को देखकर मुस्कुराते भी डरते थे। किसी को लगता था कि कहीं शिक्षक उन्हें टोक न दें, किसी को लगता था कि कहीं गलती से पत्ती छू गई तो सज़ा न मिल जाए।

लेकिन चेखव उन बच्चों की तरह नहीं थे जिनकी संवेदनाएँ डर के आहत साये में पलें। वह प्रकृति के पास जाते थे जैसे कोई नदी अपने पुराने पथ से मिल रही हो। वह फूलों की तरफ झुककर उन्हें ऐसे देखते जैसे उनमें कोई कहानी छिपी हो, कोई रंग कोई राज़ सुना रहा हो। पत्तियों की नसें उन्हें मानो जीवन की लय सिखाती थीं, और उनकी आँखों में दपदपाते रंग उन सपनों को जन्म देते थे जो साधारण बच्चों की पहुँच से परे होते हैं।

एक दिन वे चुपचाप अपनी कक्षा में गए, कागज़ और रंग उठाए, और बाहर देखे गए

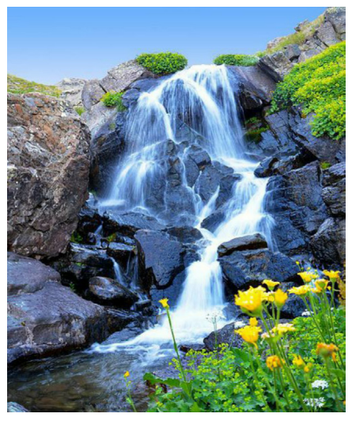

फूलों की हूबहू आकृतियाँ बनानी शुरू कर दीं। उनके चित्रों में केवल आकार नहीं थे, उनमें वे भाव थे जो किसी डरे हुए बच्चे के हाथ कभी व्यक्त नहीं कर सकते। संयोजिका को जल्द ही समझ आ गया कि यह बालक किसी नियम के दबाव में काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से चित्रांकन कर रहा है। उन्होंने चेखव को चुपचाप देखा और उनके भीतर के सृजन की लौ को पहचान लिया।

कुछ दिनों बाद चेखव की माँ को बुलाया गया। माँ के मन में आशंका थी, कि शायद बच्चा किसी शरारत में फँसा होगा। लेकिन संयोजिका की मुस्कान में किसी शिकायत की छाया नहीं थी। उन्होंने कहा—“आपका बेटा प्रकृति से सिर्फ देख कर नहीं, बल्कि महसूस कर के प्रेम करता है। यहाँ के सारे बच्चे नियमों को निभाने के लिए फूलों को देखते हैं, लेकिन यह बच्चा हर फूल को ऐसे देखता है मानो वह उससे बात कर रहा हो। इसे कला और साहित्य की राह पर आगे बढ़ने दीजिए। इसकी प्रकृति से यह जो नज़दीकी है, वही इसे एक दिन महान बना देगी।”

माँ यह सुनकर हैरान भी हुईं और गर्व भी महसूस किया कि उनका बच्चा ऐसी संवेदनशीलता लिए हुए है, जो कम उम्र में किसी को नहीं मिलती। उन्होंने संयोजिका की बात स्वीकार की और बालक चेखव ने उसी दिन से अपने भीतर के कलाकार को कभी दबने नहीं दिया।

समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। चेखव बड़ा हुआ, उसके मन के रंग और गहरे होते गए, उसके अनुभव और संवेदनाएँ और गहरी होती चली गईं। और फिर बीस साल बाद दुनिया ने देखा कि वही बच्चा, जिसे फूलों में कहानी दिखाई देती थी, कैसे एक महान लेखक बन गया। उसकी लिखी हर कहानी में एक सूक्ष्म संवेदना छिपी होती—प्रकृति के प्रति प्रेम, मनुष्य के दर्द को समझने की क्षमता, और जीवन को छोटे-छोटे पलों में बाँटकर महसूस करने की अद्भुत शक्ति।

चेखव की रचनाओं में वही मासूम बच्चा छिपा था, जो फूलों को तोड़ता नहीं था क्योंकि वह जानता था कि बिना तोड़े भी उन्हें अपने भीतर उतारा जा सकता है। उसकी कहानियों में वही मादक सुगंध थी जो उसने बचपन में फूलों से महसूस की थी। उसकी लेखनी में वही नरमी थी जो उसने कधियों पर खिलते पत्तों से सीखी थी। उसकी कला में वही मौन संगीत था जो उसे पेड़ों की छाँव में मिला था।

यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कला का जन्म किसी नियम या किसी आदेश से नहीं होता। कला का जन्म होता है एक आज़ाद मन से, उस प्रेम से जो बिना किसी डर के प्रकृति को गले लगाता है, उस दृष्टि से जो चीज़ों को देखने से ज्यादा महसूस करना जानती है।

जो बच्चा फूलों की पंखुड़ियों में कविता ढूंढ लेता है, हवा में संगीत सुन लेता है, पत्तियों में जीवन का रहस्य देख लेता है—वह बच्चा कभी साधारण नहीं होता। उसमें प्रकृति एक कलाकार को जन्म देती है।

और वही चेखव थे—प्रकृति की गोद में पला वह नन्हा कलाकार, जिसने पूरी दुनिया को अपनी कहानियों से नया दृष्टिकोण दे दिया।

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक मिसाल है

हिंदू-बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तुष्टिकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को बार-बार क्यों चोट पहुँचायी जाती है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निशाना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा? इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है; यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे ‘दीपथूण’ (पत्थर के दीप-स्तंभ) पर दीप प्रज्ज्वलन को लेकर उठा विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा ‘दीपथूण’ पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए भक्तों को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के दिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जिसके बाद रविकुमार ने अवमानना याचिका दायर की। उसी दिन न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दस भक्तों को दीपथूण तक जाने और वहाँ दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति दी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बता दें कि इस मामले की जड़ें लगभग सौ वर्ष पुरानी हैं। तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी, जो भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों (अरुपडई वीड़कु) में से एक है, वहां पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। किंतु दीप प्रज्ज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उचिपिल्लैयार कोविल मंडपम है; हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति HR&CE विभाग द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते वह दरगाह से दूर हो। इसके बाद भी दीपथूण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिन पर 2014 और 2017 में उच्च न्यायालय ने यह दोहराया था कि मंदिर प्रबंधन ही धार्मिक परंपराओं और स्थलों का निर्धारण करेगा। लेकिन इस वर्ष पुनः इस विवाद ने जोर पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी कि न्यायपालिका का अपमान करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया।

दूसरी ओर, यह विवाद इसी बीच संसद तक पहुँच गया है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी) और AIMIM से संबद्ध 107 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव सौंपा। आरोप लगाया गया कि न्यायाधीश ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निर्णय दिए और निष्पक्षता व धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा है। देखा जाये तो विपक्ष का यह कदम अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है, क्योंकि इसे न्यायपालिका पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के निर्णय से असहमति को आधार बनाकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया, वह भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व और चिंताजनक मिसाल है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का इतिहास केवल मंदिर-प्रशासन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू आस्था का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है जहाँ सदियों से भक्तों की उपस्थिति रही है। 1920 के सिविल डिक्री और प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्पष्ट कहा था कि पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है तथा दरगाह उससे केवल कुछ सीमित हिस्सों में सम्बद्ध है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि दीपथूण पर दीप जलाना मंदिर-परिसर के भीतर ही धार्मिक अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

फिर भी, पिछले तीन दशकों में दीपथूण को लेकर विवाद गहराता गया और प्रशासन ने अक्सर सुरक्षा या साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर हिंदू परंपराओं को सीमित किया।

अभियान

जब आस्था ने मोमोज और चाऊमीन को प्रसाद बना दिया

भारत की धरती पर मंदिरों की परंपराएँ जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही विविध और रोचक भी। कहीं प्रसाद में तिल के लड्डू मिलते हैं, कहीं नारियल, कहीं गुड़-चावल; लेकिन कोलकाता की चहल-पहल भरी सड़कों के बीच एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को प्रसाद में मिलता है गरमा-गरम मोमोज, सुगंध से भरी चाऊमीन और चीनी स्वाद का एहसास दिलाता फ्राइड राइस। सुनने में यह किसी मिथक जैसा लगे, पर यह सच्ची कहानी है तांग्रा क्षेत्र में स्थित काली माँ के उस मंदिर की, जिसने आस्था को सीमा और संस्कृतियों से परे जाकर अपनाया है।

इस मंदिर की विशेषता केवल इसका प्रसाद नहीं, बल्कि इसका उद्भव, इसकी वायु में तैरती दंतकथाएँ और इसके चारों तरफ फैला भारतीय-चीनी संस्कृति का रंग है। तांग्रा, जिसे सालों से चाइना टाउन कहा जाता है, कभी सांस्कृतिक मिश्रण का केंद्र हुआ करता था। संकरी गलियों में तली हुई नूडल्स की खुशबू, लाल रंग की सजावट, लटकते चीनी लालटेन और उसके बीच खड़ा

माँ काली का यह शांत मंदिर—दो संस्कृतियों का ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है।

मंदिर की कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी उसकी परंपरा। कई वर्ष पहले इसी इलाके में एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर इलाज से थक चुके थे और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। बच्चे के माता-पिता टूट गए थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उस समय इस स्थान पर केवल एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर रखकर काली माँ की पूजा होती थी। परिवार ने टूटे मन से बच्चा वहीं लिटा दिया और कहा—

“माँ, यदि हमारा बेटा जीवित हो गया तो हम यहीं एक मंदिर बनवाएँगे।”

कहते हैं, जैसे किसी चमत्कार ने उस स्थान को स्पर्श कर लिया हो, बच्चा उस पेड़ के नीचे उठकर बैठ गया। घरवालों की आँखों में भय, विस्मय और कृतज्ञता एक साथ तैरने लगीं। उस क्षण से यह स्थान साधारण नहीं रहा। यहाँ माँ काली की उपस्थिति महसूस की जाने लगी, और कुछ सालों में एक सुंदर मंदिर का रूप ले लिया।

लेकिन इस मंदिर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तांग्रा क्षेत्र में रहने वाले चीनी परिवार, जो सिविल वॉर के दौरान यहाँ आ बसे थे, अपनी आस्था और अपनी जीवनशैली दोनों लेकर आए थे। जब उन्होंने काली माँ के इस चमत्कार के बारे में सुना, तो उन्होंने देवी को वही भोग चढ़ाया जो उनके लिए प्रेम और स्वाद का प्रतीक था—चाऊमीन, मोमोज और फ्राइड राइस।

उनके लिए यह भोजन केवल खाना नहीं था, यह घर की याद, संस्कृति की महक और उनके जीवन का हिस्सा था। और जब उन्होंने प्रेम से ये व्यंजन माँ को अर्पित किए, तो यह परंपरा बन गई।

आज भी इस मंदिर में हिंदू और चीनी दोनों समुदाय समान श्रद्धा से आते हैं। अगरबत्तियों की खुशबू में तली हुई नूडल्स की महक घुल जाती है और यह दृश्य बताता है कि आस्था का कोई भाषा नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई सीमा नहीं होती। हर भक्त यहाँ मोमोज को प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, और अजीब बात यह है कि उस प्रसाद में भी वही भाव होता है जो किसी मंदिर के लड्डू में मिलता है—भक्ति, कृतज्ञता और माँ की कृपा।

कोलकाता का यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह उस सच का स्मारक है कि जब आस्था और प्रेम मिलते हैं, तो संस्कृतियाँ दीवार नहीं बनातीं, पुल बन जाती हैं।

और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है—यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के सामने किसी का भोजन छोटा-बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है हृदय की सच्चाई, और वही सच्चाई मोमोज के हर कौर में महसूस की जा सकती है।

यदि कभी आप कोलकाता जाएँ, तो तांग्रा की गलियों में उतरिए। वहाँ की हवा में चाऊमीन की खुशबू और मंदिर की घंटियों की ध्वनि मिलकर एक अनोखा संसार रचती है। और जब आप वहाँ का प्रसाद चखेंगे, तो समझ आएगा कि कभी-कभी चमत्कार मोमोज के स्वाद में भी मिल जाता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

'ग्रीन गुजरात, विकसित गुजरात' : पिछले 3 वर्ष में 1.04 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में बुवाई कार्य किया गया

- सामाजिक वनीकरण योजना अंतर्गत ग्रीन कवर में उल्लेखनीय वृद्धि, पिछले 3 वर्ष में वन क्षेत्र से बाहर 10,213 हेक्टेयर क्षेत्र में विभागीय बुवाई पूर्ण
- वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए गुजरात सरकार द्वारा बजट में 3,140 करोड़ रुपए का प्रावधान
- पिछले 3 वर्ष में स्थानीय आदिवासी समुदायों को कुल 158 लाख बाँस का वितरण किया गया
- 'मिष्टी' योजना के क्रियान्वयन में अग्रसर गुजरात, पिछले 3 वर्ष में कुल 34,242 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव की बुवाई की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : आगामी 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सुशासन के तीन वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार 'ग्रीन गुजरात, विकसित गुजरात' के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्यरत है। पिछले 3 वर्ष में गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए व्यापक पैमाने पर बुवाई एवं पुनर्वनीकरण किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह विशिष्ट मॉडल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप है। पिछले तीन वर्ष में गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण तथा हरितावरण बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें एक उल्लेखनीय प्रयास वन क्षेत्र में बुवाई बढ़ाना है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कुल 1,04,270 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। इतना ही नहीं; केन्द्र सरकार की 'मिष्टी' योजना के क्रियान्वयन में भी गुजरात अग्रसर राज्य है।

'मिष्टी' योजना अंतर्गत गुजरात में 34,242 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई मैंग्रोव की बुवाई

मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम (मिष्टी) योजना अंतर्गत समुद्र तट पर मैंग्रोव वन सृष्टि का विस्तार करते हुए कुल 34,242 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव की बुवाई की गई है। 'मिष्टी' योजना केन्द्र सरकार ने 5 जून, 2023 को तटवर्ती राज्यों में मैंग्रोव इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की थी; जिसका मुख्य उद्देश्य मैंग्रोव बुवाई, मैंग्रोव क्षेत्र की वैज्ञानिक मैपिंग, नर्सरी विकास, हाइड्रोलॉजी-भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन, जन जागृति, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन देकर तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना है।

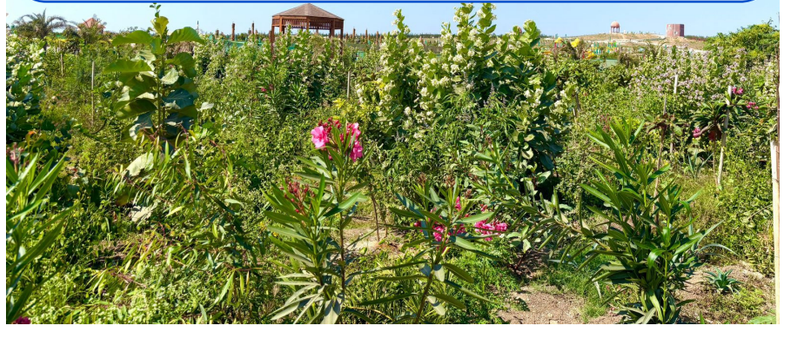

सामाजिक वनीकरण योजना : पिछले 3 वर्ष में 10,213 हेक्टेयर क्षेत्र में विभागीय बुवाई पूर्ण

वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में वनावरण बढ़ाने के लिए पिछले 3 वर्ष में कुल 1,04,270 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई कार्य किया गया है, जबकि वन क्षेत्र से बाहर हरितावरण बढ़ाने के लिए सामाजिक वनीकरण योजना अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में कुल 10,213 हेक्टेयर क्षेत्र में विभागीय बुवाई कार्य किया गया है। इसके अलावा; राज्य के किसानों को वन विभाग की विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके कारण पिछले तीन वर्ष में किसानों द्वारा 1,09,425.60 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

भावी पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य का निर्माण करने का गुजरात का दृढ़ संकल्प

ग्रीन कवर पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह जलवायु स्थिरता, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, जैवविविधता बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता करता है। विशेषकर मैंग्रोव समुद्री जीव सृष्टि को समर्थन देने, समुद्र तट को स्थिर रखने और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव कम करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुजरात दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखकर पर्यावरण को संरक्षित रखने एवं भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ हरित भविष्य बनाने को प्रतिबद्ध है। पर्यावरण जतन के लिए राज्य सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 2025-26 के बजट में कुल 3,140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पिछले तीन वर्ष में स्थानीय आदिवासी समुदायों को कुल 158 लाख बाँस का वितरण

राज्य सरकार ने परंपरागत घास-चारे की पुनर्स्थापना तथा वनाधारित जीवन को समर्थन देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पिछले 3 वर्ष में कच्छ के बन्नी क्षेत्र में कुल 5,000 हेक्टेयर में घास-चारे की बुवाई करके विभागीय घास-चारा संग्रह के अलावा अनुमानित 52.52 लाख किलोग्राम घास-चारे का स्थानीय लोगों को वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त; राज्य में पिछले तीन वर्ष में स्थानीय आदिवासी समुदायों को कुल 158 लाख बाँस का वितरण किया गया है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन, वडोदरा – कोट्टयम तथा साबरमती – नई दिल्ली स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 04005/04006 बांद्रा टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 04005 बांद्रा टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को 14.40 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.10 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04006 हज़रत निज़ामुद्दीन – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को 13.35 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम एवं कोटा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर एवं एसी-3 टियर कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09124/09123 वडोदरा – कोट्टयम (साप्ताहिक) स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09124 वडोदरा – कोट्टयम स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 09.05 बजे वडोदरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19.00 बजे कोट्टयम पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09123 कोट्टयम – वडोदरा स्पेशल प्रत्येक रविवार को 21.00 बजे कोट्टयम से प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 06.00 बजे वडोदरा पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 दिसम्बर, 2025 से 11 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमली, मडगांव, कारवार, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मुकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंडापुरा, उडुपी, सुरथकल, मंगलुरु जं., कासरगोड, कन्नूर, तलश्शेरी, कोझिक्कोड, तिरुर, षोरनूर, त्रिशूर, आलुवा तथा एरणाकुलम टाउन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 04033 साबरमती – नई दिल्ली स्पेशल (01 फेरा)

ट्रेन संख्या 04033 साबरमती – नई दिल्ली स्पेशल गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को 19.00 बजे साबरमती से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

यह ट्रेन पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर एवं रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर एवं एसी-3 टियर कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04005 एवं 04033 की बुकिंग शुरू है, जबकि ट्रेन संख्या 09124 की बुकिंग 12.12.2025 से समस्त पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री समस्त पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए वडोदरा और कोट्टायम के बीच चलायी जाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे द्वारा वडोदरा और कोट्टायम के बीच स्पेशल किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09124/09123 वडोदरा – कोट्टायम साप्ताहिक स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09124 वडोदरा – कोट्टायम साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को वडोदरा से 09.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19:00 बजे कोट्टायम पहुँचेगी। यह ट्रेन 20 दिसंबर, 2025 से 10 जनवरी,2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09123 कोट्टायम - वडोदरा साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार को कोट्टायम से 21.00 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 06:00 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 दिसंबर, 2025 से 11 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, कारवर, कुमटा, मुद्रेश्वरा, भटकल, मूकाम्बिका रोड बायनूर, कुन्दापुरा, उडिपी, सूरथकल, मैंगलोर, कासरगोड़, कन्नूर, थालासेरी, कोझिकोड, तिरुर, शोनारूर जंक्शन, थ्रिसूर, अलुवा और एरनाकुलम स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, शयनयान कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09124 की बुकिंग 12 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, रेलवे अमृत भारत स्कीम के तहत 1,300 से अधिक स्टेशनों का कर रहा है पुनर्विकास

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 10 दिसंबर:2025 को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के चल रहे रेलवे स्टेशन पुनर्विकास अभियान के पैमाने और प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की। मंत्रीश्री ने कहा, "मैं पूरे सदन और राष्ट्र को, आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास की एक नई पहल शुरू की है, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश द्वारा स्टेशनों के पुनर्विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।"

1,300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, 160 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, और यह काम करने के पुराने पारंपरिक तरीकों से अलग है जहां सिर्फ रंग-रोगन को ही स्टेशन विकास मान लिया जाता था। आज हम एक सुविचारित मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे हैं, स्थानीय वास्तुकला को महत्व दे रहे हैं, दोनों ओर से प्रवेश का रास्ता बना रहे हैं, यात्री हॉल और एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) बना रहे हैं, और आने वाले अगले 50 वर्षों के लिए इसकी योजना बना रहे हैं।

श्री वैष्णव ने सुधारे गए प्रवेश क्षेत्रों, विस्तारित पार्किंग ज़ोन और नई यात्री-प्रबंधन व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश डाला। दिवाली और छठ पूजा के दौरान तैयार किए गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया का उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे चरम त्योहारी भीड़ के दौरान हजारों यात्री रेलवे सुविधाओं का उपयोग करते हुए आराम से इंतजार कर पाए। स्टेशनों पर बढ़ी हुई स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मंत्रीश्री ने कहा कि 15 साल पहले की स्थिति की तुलना में स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए "एक नया मानक" स्थापित हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल जून में अमृत भारत स्टेशनों के एक नए समूह के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया था, जिसमें राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 103 स्टेशनों को लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रव्यापी आधुनिकीकरण प्रयास में एक और मील का पत्थर था। उन्नत मुहार, बेहतर परिसंचरण क्षेत्रों, टिकाऊ भवन सुविधाओं और बहु-मोडल एकीकरण के साथ योजनाबद्ध ये स्टेशन, देश भर में विश्व-स्तरीय, भविष्य के लिए तैयार रेलवे हब बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।

11 दिसंबर को चलेगी साबरमती और नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के तहत साबरमती और नई दिल्ली के बीच विशेष किराये पर आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 04033/04034 साबरमती-नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 04033 साबरमती-नई दिल्ली स्पेशल 11 दिसंबर 2025 को साबरमती से 19.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13.40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04034 नई दिल्ली–साबरमती स्पेशल 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 16.40 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं., ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी I-टियर, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 04033 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भारत की रफ्तार पर एडीबी का भरोसा और बढ़ा: 2025–26 के लिए विकास दर का अनुमान 7.2% तक पहुंचा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को अपनी राय बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी क्रम में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बुधवार को जारी अपनी ताज़ा एशिया विकास परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर अनुमान में बड़ा संशोधन किया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है—यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस मजबूत आर्थिक आधार का संकेत है जिसकी बदौलत भारत वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है।

रिपोर्ट बताती है कि GST दरों में हाल में हुई कटौती से घरेलू खपत में अप्रत्याशित तेजी आई है। विनिर्माण और सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है, निवेश का स्तर ऊपर जा रहा है, और उपभोक्ता विश्वास में स्थिरता लौट रही है। इन सभी कारकों ने मिलकर अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है।

पालघर में गैस सिलेंडर चोरी गैंग का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

(जीएनएस)। पालघर जिले में पिछले कई हफ्तों से आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और निजी बंगलों में ताले तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी किए जाने की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और प्रशासन दोनों को चिंता में डाल रखा था। लोगों द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई संगठित गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है जो योजनाबद्ध ढंग से वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सफाला और केलवा पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में गैस सिलेंडर चोरी की कुल चार वारदातें दर्ज की गईं, जिनमें सफाला पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 161/2025, 162/2025 और 163/2025 तथा केलवा सागरी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 73/2025 शामिल थे। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई और छानबीन के दौरान तकनीकी विश्लेषण, घटनास्थलों का निरीक्षण तथा गोपनीय सूत्रों की मदद से पुलिस धीरे–धीरे इस गैंग के करीब पहुंचने लगी। जांच के दौरान दो ऐसे संदिग्धों पर पुलिस का ध्यान गया जो चोरी की घटनाओं वाले क्षेत्रों में अक्सर देखे गए थे। सुराग पुख्ता होने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और आखिरकार उन्होंने चोरी की चारों वारदातों में शामिल होने की बात कबूल कर ली।

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान अजय एकनाथ आंबात, उम्र 32 वर्ष, निवासी बंदाटे, तालुका पालघर और चंदू रमेश वळवी, उम्र 25 वर्ष, निवासी देवशेत, तालुका पालघर के रूप में हुई है। दोनों आरोपी रात के समय सुनसान स्थानों को निशाना बनाकर ताले तोड़ते थे और गैस सिलेंडर चुराकर उन्हें स्थानीय स्तर पर सस्ते दामों पर बेच देते थे, जिससे उन्हें अवैध कमाई होती थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इनके ठिकानों की तलाशी ली तो वहां से कुल 25 गैस सिलेंडर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,28,000 रुपये आँकी गई है। इन बरामदियों ने न केवल आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि की बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे काफी समय से इस अवैध धंधे में शामिल थे और चोरी को ही आय का प्रमुख साधन बना रखा था। सफाला पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रहा है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं या चोरी किए गए सिलेंडरों की सप्लाई लाइन कहीं और तक फैली हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि जांच में किसी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी अधिकारी सपोनि दत्ता शेलके के नेतृत्व में सफाला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस के सामूहिक प्रयास, तत्परता और सटीक विश्लेषण के कारण यह मामला सुलझ पाया और गैस सिलेंडर चोरी के सिलसिले पर फिलहाल अंकुश लगने की उम्मीद जगी है। स्थानीय निवासियों ने इस सफलता पर राहत व्यक्त की है और उम्मीद जताई है कि ऐसे अपराधों पर पुलिस की पकड़ आगे भी मजबूत बनी रहेगी।

चांदी वायदा 191800 रुपये के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचा: सोना वायदा में 196 रुपये की नरमी

क्रूड ऑयल वायदा 38 रुपये बढ़ा: कमोडिटी वायदाओं में 31104.59 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 118729.57 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 25569.96 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31620 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 149838.25 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 31104.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 118729.57 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31620 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2213.82 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 25569.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 130339 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 130502 रुपये और नीचे में 129700 रुपये पर पहुंचकर, 130107 रुपये के पिछले बंद के सामने 196 रुपये या 0.15 फीसदी औंधकर 129911 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 131 रुपये या 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 104250 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 4 रुपये या 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 13061 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 129160 रुपये के भाव पर खूलकर, 129163 रुपये के दिन के उच्च और 128415 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 190 रुपये या 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ 128663 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 129272 रुपये के भाव पर खूलकर, 129539 रुपये के दिन के उच्च और 128731 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129166 रुपये के पिछले बंद के सामने 136 रुपये या 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 129030 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 188959 रुपये के भाव पर खूलकर, 191800 रुपये के ऑल टाइम हाई और 188800 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 188064 रुपये के पिछले बंद के सामने 2079 रुपये या 1.11 फीसदी की मजबूती के साथ 190143 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 2111 रुपये या 1.12 फीसदी बढ़कर 190675 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 2161 रुपये या 1.15 फीसदी की बढ़त के साथ 190732 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 2599.54 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 12.2 रुपये या 1.13 फीसदी बढ़कर 1091.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 40 पैसे या 0.13 फीसदी के सुधार के साथ 310.95 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.15 रुपये या 0.42 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 276.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 40 पैसे या 0.22 फीसदी के सुधार के साथ 181.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2989.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5273 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5289 रुपये और नीचे में 5238 रुपये पर पहुंचकर, 38 रुपये या 0.72 फीसदी बढ़कर 5284 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 36 रुपये या 0.69 फीसदी की मजबूती के साथ 5285 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 417.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 417.6 रुपये के दिन के उच्च और 402.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 421.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 18.3 रुपये या 4.34 फीसदी लुढ़ककर 403.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 18.8 रुपये या 4.45 फीसदी की गिरावट के साथ 403.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 906.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 70 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 905 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8952.35 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 16617.61 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2123.56 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 148.91 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.97 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 316.10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 500.18 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2474.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15188 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 72063 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20086 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 341306 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 34681 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 18277 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40710 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 117920 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17179 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 30748 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 31641 पॉइंट पर खूलकर, 31720 के उच्च और 31541 के नीचले स्तर को छूकर, 48 पॉइंट बढ़कर 31620 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 7.8 रुपये की बढ़त के साथ 72.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 8.7 रुपये की गिरावट के साथ 17.25 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 145.5 रुपये की गिरावट के साथ 2181 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 190000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1137.5 रुपये की बढ़त के साथ 6570 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.05 रुपये की बढ़त के साथ 15.95 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 14 पैसे के सुधार के साथ 2.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 24.9 रुपये की गिरावट के साथ 92.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 9.6 रुपये की बढ़त के साथ 23.6 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 124000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 8.5 रुपये की बढ़त के साथ 457.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 423.5 रुपये की गिरावट के साथ 2388.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.95 रुपये की गिरावट के साथ 13.59 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 38 पैसे के सुधार के साथ 0.8 रुपये हुआ।

सीबीआई ने वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया, विभाग में हड़कंप

(जीएनएस)। गाजियाबाद। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद में तैनात वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा को आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुंबई से हिरासत में लेकर मंगलवार को गाजियाबाद स्थित सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस गिरफ्तारी के बाद पासपोर्ट विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों के बीच सुरक्षा व निगरानी कड़ी कर दी गई है।

जांच से पता चला है कि दीपक चंद्रा ने वर्ष 2018 से 2024 के बीच पासपोर्ट अधीक्षक, सहायक पासपोर्ट अधीक्षक और वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक के पदों पर रहते हुए अपनी ज्ञात आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की। प्रारंभिक जांच में उनके नाम और परिवारजनों के माध्यम से करीब 1.43 करोड़ रुपये मूल्य की संदिग्ध संपत्ति पाई गई है। इस संपत्ति में नकद राशि, बैंक जमा, अचल संपत्ति, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं।

सीबीआई ने गाजियाबाद और पटना में तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान लगभग 60 लाख रुपये नकद, अचल संपत्ति के दस्तावेज, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए। इन दस्तावेजों की जांच से यह पता लगाया जाएगा कि संपत्ति अर्जित करने में कौन-कौन शामिल था और क्या यह संपत्ति किसी संगठित नेटवर्क के तहत अर्जित की गई थी।

एजेंसी के अनुसार, दीपक चंद्रा की वैध आय केवल 1,29,557 रुपये थी, जबकि उनके पास कुल 88.43 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति पाई गई। आय और संपत्ति के बीच यह बड़ा अंतर इस मामले को बेहद गंभीर बनाता है। रिमांड अवधि में सीबीआई आरोपी से यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस संपत्ति के निर्माण में अन्य अधिकारियों या बाहरी व्यक्तियों की क्या भूमिका थी और क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी शामिल थी।

इस गिरफ्तारी और तलाशी अभियान के बाद पासपोर्ट विभाग में कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अन्य कर्मचारियों के लिए चेतावनी स्वरूप है और आने वाले दिनों में सीबीआई और कड़े कदम उठा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता को उजागर करता है।

सीबीआई इस मामले की जांच में यह भी देख रही है कि आरोपी ने इतनी बड़ी राशि अर्जित करने के लिए किन माध्यमों और तरीकों का इस्तेमाल किया। जांच का दायरा अब इस बात तक बढ़ाया गया है कि क्या इस संपत्ति अर्जन में पासपोर्ट विभाग के अन्य अधिकारी या बाहरी एजेंट शामिल थे और क्या इसमें किसी तरह की नेटवर्किंग और योजनाबद्ध रूप से गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इस गंभीर मामले ने न केवल पासपोर्ट विभाग में बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र में चेतावनी की लहर दौड़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई आगामी दिनों में और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिससे ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही को अंजाम न दिया जा सके और सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

नक्सल हिंसा के साए से बाहर आती ज़िंदगियां: गढ़चिरौली में 82 लाख के 11 कुख्यात नक्सलियों का आत्मसमर्पण

(जीएनएस)। गढ़चिरौली का घना वनक्षेत्र, वर्षों से नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाने वाला यह इलाका बुधवार को एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने इलाके की हवा में एक नई उम्मीद का संचार किया। बारूदी सुरंगों और गोलियों की आवाज़ों से पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में पहली बार शांति का सुर कुछ अधिक स्पष्ट सुनाई दिया, जब 11 खतरनाक और लंबे समय से वांछित नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए।

यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक सुरक्षा अभियान की सफलता नहीं, बल्कि उन लोगों की वापसी भी है जिन्होंने हिंसा के रास्ते से लौटकर जीवन और समाज की मुख्यधारा को चुना है। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम ने गढ़चिरौली में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की गहरी प्रभावशीलता को दर्शाया।

इन 11 नक्सलियों पर कुल मिलाकर 82 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें डिवीजनल कमेटी, प्लाटून कमेटी और एरिया कमेटी के स्तर पर काम करने वाले ऐसे सदस्य शामिल थे, जिनके नाम से आदिवासी गांवों में दहशत पैदा होती थी। रमेश उर्फ भीमा लेकामी, भीमा उर्फ किरण हिडमा कोवासी, पोरीये उर्फ लकी गोटा और रतन उर्फ सन्ना मासु ओयाम जैसे नाम वर्षों से सुरक्षा बलों की सूची में सबसे ऊपर थे।

चार नक्सलियों ने हथियार और वर्दी के साथ मंच पर उपस्थित होकर इस बात का संकेत दिया कि वे अब हिंसा का रास्ता पीछे छोड़ चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक-एक कदम संतुलन और सतर्कता के साथ उठाया गया। फिर भी वातावरण में एक अलग किस्म की राहत थी—मानो जंगलों की खामोशी भी उनकी इस वापसी को सुन रही हो। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जो सुरक्षा बलों ने इलाके में किया है। इससे पहले 15 अक्टूबर को वरिष्ठ माओवादी नेता सोनू मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने 61 साथियों के साथ समर्पण कर दंडक क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया था। यह नई घटना उसी शृंखला का अगला कदम है, जो इस इलाके में माओवादी संगठन की कमजोर होती पकड़ को स्पष्ट करती है।

डीजीपी रश्मि शुक्ला ने मौके पर मौजूद सी-60 कमांडो दस्ते की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने उन जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए नक्सल गतिविधियों को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौटना नक्सलियों के लिए नया जीवन पाने जैसा है, और बाकी बचे माओवादियों को भी हिंसा छोड़कर इसी रास्ते पर चलना चाहिए।

कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई—'प्रोजेक्ट उड़ानः विज़न ऑफ डेवलपमेंट'। इस गाइडबुक का उद्देश्य दूरदराज के जंगल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकार की सभी विकास योजनाओं को सरल भाषा में समझाना है, ताकि जो लोग अब तक नक्सलवाद के कारण विकास से कटे हुए थे, वे सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठा सकें।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वटवा में बनेगा मेगा कोचिंग टर्मिनल

अहमदाबाद क्षेत्र से 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन होगा संभव,अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का लोड कम होगा, संचालन होगा और भी सुगम

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वटवा में लगभग 3 किमी का एक मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का अत्यधिक लोड काफी हद तक कम होगा और पूरे क्षेत्र में ट्रेन संचालन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। यह परियोजना मंडल की 2.5 गुना ट्रेन हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बेहतर यात्री सुविधा, निर्बाध संचालन तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक रेलवे ढांचा तैयार करना है।

वटवा टर्मिनल की मुख्य संरचना और आधुनिक सुविधाएँ

▸▸ वटवा का यह मेगा टर्मिनल लगभग 3 किमी लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई LC-305 पर 76 मीटर, ROB-713 (SP रिंग रोड) पर 300 मीटर तथा खारी ब्रिज नं. 711 पर 118 मीटर रहेगी।

▸▸ टर्मिनल में कुल 12 पिट लाइनें बनाई जा रही हैं, जिनसे ट्रेनों का गहन व नियमित मेंटेनेंस आसानी से संभव होगा।

▸▸ 29 स्टेबलिंग लाइनें उपलब्ध कराई जाएँगी, जिनमें खाली रेक सुरक्षित खड़े किए जा सकेंगे।

▸▸ 2 वॉशिंग लाइनें बनाई जाएँगी, जिनसे रेक की तेज़ और निरंतर सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

▸▸ 2 सिक लाइनें (600 मीटर) बनाई जा रही हैं, जहाँ खराब कोचों की मरम्मत और तकनीकी सुधार किए जा सकेंगे।

▸▸ 6 नए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएँगे, जिससे प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या 9 हो जाएगी और ट्रेनों का आरंभ व समाप्ति अधिक सुव्यवस्थित होगी।

▸▸ वटवा टर्मिनल के पूर्ण संचालन के बाद प्रतिदिन 36 जोड़ी ट्रेनों का प्राइमरी मेंटेनेंस, 15 ट्रेनों की प्लेटफॉर्म रिटर्न सुविधा और कुल 51 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।

▸▸ अकेले वटवा टर्मिनल ही मंडल की कुल क्षमता वृद्धि में लगभग 85% योगदान देगा।

अहमदाबाद मंडल में व्यापक क्षमता वृद्धि – सभी स्टेशनों पर तेजी से चल रहा विकास

▸▸ वटवा के साथ-साथ अहमदाबाद, साबरमती, असारवा, गांधी नगर कैपिटल और गांधीग्राम स्टेशनों पर भी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन कार्य जारी हैं, जो पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाएँगे।

▸▸ सभी कार्य पूर्ण होने पर मंडल की ट्रेन ओरिजिनेशन क्षमता औसत 58 से बढ़कर 150 प्रतिदिन हो जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि होगी।

▸▸ अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन संचालन क्षमता 38 ट्रेनों से बढ़कर 45–50 ट्रेनों प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

▸▸ साबरमती स्टेशन पर यह क्षमता 20 से बढ़कर 27–28 ट्रेन प्रतिदिन होगी।

▸▸ असारवा स्टेशन पर क्षमता 6 से बढ़कर 11–12 ट्रेन प्रतिदिन तक बढ़ेगी।

▸▸ गांधी नगर कैपिटल स्टेशन की क्षमता 6 से बढ़कर 8–10 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

▸▸ गांधीग्राम स्टेशन 4 से बढ़कर 7–8 ट्रेन प्रतिदिन का संचालन करने में सक्षम होगा।

▸▸ वटवा स्टेशन की संचालन क्षमता सबसे अधिक वृद्धि के साथ 6 से बढ़कर 56–57 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँचेगी।

यात्रियों को बड़े लाभ और रणनीतिक नेटवर्क सुधार

▸▸ क्षमता वृद्धि से यात्रियों को प्रतिदिन की यात्री वहन क्षमता 1,02,000 से बढ़कर 2,62,000 प्रतिदिन (लगभग 2.5 गुना) तक का लाभ मिलेगा।

▸▸ अधिक संख्या में एक्सप्रेस, MEMU, फेस्टिवल स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की शुरुआत संभव होगी।

▸▸ पिट लाइन बनने से 23-कोच LHB रेक, वंदेभारत एवं अमृत भारत जैसी ट्रेनों का मेंटेनेंस संभव होगा जिससे ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी।

▸▸ अहमदाबाद और साबरमती यार्ड में भीड़ कम होने से ट्रेनों की समयपालनता में वृद्धि होगी।

▸▸ तेज़ मेंटेनेंस और कम टर्नअराउंड समय से ट्रेन संचालन अधिक सुचारु, समयबद्ध और कुशल बनेगा।

▸▸ नई पिट लाइन, स्टेबलिंग, वॉशिंग और सिक लाइन सुविधाएँ रेक की बेहतर सफाई, गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करेंगी।

▸▸ अहमदाबाद यार्ड रीमॉडलिंग, साबरमती में नई पिट लाइन व प्लेटफॉर्म निर्माण, असारवा–साबरमती Y-कनेक्शन तथा गांधीग्राम–साबरमती–खोड़ियार Y-कनेक्शन जैसे प्रमुख नेटवर्क सुधार कार्य ट्रेन मूवमेंट को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध बनाएँगे।

इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का सबसे सक्षम, आधुनिक और भविष्य-उन्मुख टर्मिनल क्लस्टर बनकर उभरेगा, जो प्रतिदिन 150 ट्रेनों का संचालन दक्षता से कर सकेगा। यह यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार लाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर सेक्शन में पेच डबलिंग कमीशनिंग और मऊ-खुरहट प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

आंशिक निरस्त ट्रेनें

16 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी तथा वाराणसी - गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से ओरिजिनेट (प्रारंभ) होगी तथा गोरखपुर - वाराणसी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल/रेगुलेट ट्रेनें

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस अहमदाबाद से 4 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

9, 10 और 11 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 50 मिनट रेगुलेट (विलंब) होगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेन

15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज और अयोध्या केंट स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

10,13 और 15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज, आजमगढ़, मऊ और बलिया स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे में सक्रिय रूप से आयोजित किया गया "डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 4.0 अभियान" 125 शिविरों में 4,355 पेंशनभोगियों को मिला लाभ

(जीएनएस)। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप, पश्चिम रेलवे ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक आयोजित राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से सहभागिता की।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता के माध्यम से पेंशनभोगियों को सशक्त बनाना तथा एंड्रॉइड एवं आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 'जीवन प्रमाण' मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सरलता से जमा करने की सुविधा प्रदान करना है।

मुंबई सेंट्रल मंडल के लेखा विभाग द्वारा स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, रेलवे कॉलोनी तथा वलसाड रेलवे स्टेशन पर डीएलसी शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 42 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों ने भाग लिया। विशेष रूप से, सात दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए गए, जिनमें 103 वर्षीय वरिष्ठ पेंशनभोगी भी शामिल थीं, जो यात्रा करने में असमर्थ थीं। इसके अलावा, 25 पेंशनभोगियों ने स्टेशन पर अपना डीएलसी बनवाया तथा अन्य 10 पेंशनभोगियों को डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों एवं कार्यशालाओं ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित इस अभियान को सफल बनाने हेतु सक्रिय योगदान दिया। पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों व बैंक शाखाओं में प्रतिदिन लगभग डीएलसी शिविर आयोजित किए गए। अस्पतालों में भर्ती पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए रेलवे अस्पतालों एवं मेडिकल यूनिट्स में विशेष व्यवस्थाएँ की गईं, ताकि उनके डीएलसी समय पर बनाए जा सकें।

इस वर्ष, उन पेंशनभोगियों के लिए डोर-स्टेप सेवा भी उपलब्ध कराई गई, जो बैंक तक नहीं पहुँच सकते थे। इस अभियान को व्यापक प्रतिक्रिया मिली तथा माह में आयोजित 125 शिविरों के माध्यम से कुल 4,355 पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों ने अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए।

11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे बाद खेडब्रह्मा स्टेशन पर आरक्षण सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के खेडब्रह्मा रेलवे स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने के कारण 11 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे के बाद आरक्षण सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि दोपहर 12:00 बजे से पूर्व अपने आरक्षण करा लें या फिर IRCTC वेबसाइट/ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा का उपयोग करें।

अजमेर–मदार सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर–मदार सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 44 पर रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य हेतु 11 व 12 दिसंबर, 2025 को ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इस दौरान अजमेर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

11 दिसंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी।

11 दिसंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी।

12 दिसंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी। इस दौरान उपर्युक्त ट्रेनें अजमेर स्टेशन पर नहीं जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दौराई एवं मदार जंक्शन स्टेशनों पर इन ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करे। ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डिजिटल स्किलिंग और रोजगार में बड़ा कदमः माइक्रोसॉफ्ट और श्रम मंत्रालय ने मिलाया हाथ, युवाओं के लिए खुलेंगे वैश्विक अवसर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में रोजगार और डिजिटल क्षमताओं को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बुधवार को उठाया गया, जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी न केवल तकनीक-आधारित कौशल विकास को नई ऊंचाई देगी, बल्कि लाखों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारों से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्या नडेला मौजूद थे। यह दृश्य खुद इस बात का प्रतीक था कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक टेक जगत अब पहले से कहीं अधिक करीब आ रहे हैं।

इस समझौते का मूल लक्ष्य है—एआई आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देना, युवाओं को उद्योग-तैयार बनाना और नेशनल करियर सर्विस (NCS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाई-ग्रोथ सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया है कि वह अपने वैश्विक नेटवर्क की 15,000 से अधिक कंपनियों और पार्टनर्स को एनसीएस से जोड़ेगा, जिससे युवाओं को सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नौकरी तलाशने का मौका मिलेगा।

डॉ. मांडविया ने कहा कि यह साझेदारी भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाएगी। उनकी नजर में एनसीएस पोर्टल पर माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स का जुड़ना एक ऐसा कदम है, जो आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं के करियर की दिशा बदल देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है—एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करना, जो डिजिटल, सुरक्षित और सभी के लिए समान अवसर प्रदान कर सके।

दूसरी ओर सत्या नडेला ने भारत के सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क में आए परिवर्तन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 64.3% सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक पहुंचना किसी भी विकासशील देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके माध्यम से 94 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। नडेला ने ई-श्रम पोर्टल की विशेष प्रशंसा की, जिसने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा दायरे में लाकर एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की है।

श्रम मंत्रालय का मानना है कि यह समझौता भारत को औपचारिक रोजगार के व्यापक दायरे में ले जाने, तेज़ी से बढ़ते उद्योगों को कुशल प्रतिभा उपलब्ध कराने और भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सहयोग भविष्य में भारत को न सिर्फ "स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड" बनाने दिशा में ले जाएगा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा।

इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट का बड़ा कदम, शीतकालीन सत्र में रोजाना 100 नई उड़ानों की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। घरेलू विमानन क्षेत्र में हालिया उथल-पुथल के बीच स्पाइसजेट ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जिसने यात्रियों और उद्योग दोनों को नई उम्मीद दी है। इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट के चलते जहां हजारों यात्री परेशान हैं, वहीं स्पाइसजेट ने घोषणा की है कि वह इस शीतकालीन सत्र में रोजाना 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने जा रही है। यह कदम न केवल मौजूदा क्षमता की भारी कमी को दूर करेगा बल्कि विमानन बाजार में स्थिरता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्पाइसजेट ने अपने बयान में कहा कि प्रमुख रूटों पर मांग तेजी से बढ़ रही है और यात्रियों को विकल्प देने के लिए अतिरिक्त उड़ानों की तत्काल आवश्यकता है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि नियामक संस्थाओं से अंतिम मंजूरी मिलते ही नई उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस कदम को इंडिगो की हालिया 10% फ्लाइट कटौती के बीच एक साहसिक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सख्त हिदायतों के बाद इंडिगो बड़े पैमाने पर परिचालन समायोजन कर रही है, जिससे बाजार में उड़ानों की कमी महसूस की जा रही है। स्पाइसजेट के इस विस्तार के पीछे एक मजबूत तैयारी भी है। पिछले दो महीनों में एयरलाइन 17 विमान फिर से सेवाओं में शामिल कर चुकी है—इनमें डैम्प-लीज्ड एयरक्राफ्ट के साथ-साथ वे विमान भी शामिल हैं जो लंबे समय से ग्राउंडेड थे। पिछले ही महीने कंपनी ने पांच नए बोइंग 737 विमान अपने बेड़े में जोड़े, जिनमें आधुनिक Boeing 737 MAX भी शामिल है।

इस तरह सिर्फ एक महीने में स्पाइसजेट ने 15 नए एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में शामिल किए, जिससे उसकी क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि जब पूरा विमानन सेक्टर मांग और आपूर्ति के असंतुलन से जूझ रहा है, ऐसे समय स्पाइसजेट का यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। अमेरिका और यूरोप के कई रूटों पर सीधी कनेक्टिविटी और घरेलू सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह विस्तार भारतीय विमानन बाजार के लिए बेहद सकारात्मक माना जा रहा है। स्पाइसजेट के अनुसार, नई उड़ानों का उद्देश्य केवल क्षमता बढ़ाना नहीं बल्कि उन रूटों पर सेवा को मजबूत करना है जहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंडिगो संकट के बीच यह कदम स्पाइसजेट के लिए बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर भी बन सकता है।